भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2961
बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भूमण्डलीय तापमान में वृद्धि

2961. श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भूमण्डलीय तापमान वृद्धि की सुरक्षित सीमा में रहने के लिए विश्व को वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कटौती करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उत्सर्जन-स्तर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उत्सर्जन को खतरे के स्तर से नीचे रखने के लिए पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की शून्य उत्सर्जन स्तर प्राप्त करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र के इंटरगर्वनमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की नवीनतम वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43 प्रतिशत कटौती किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) एवं (ग) भारत सरकार नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) तथा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (SAPCC) जैसी पहलों एवं विभिन्न कायर्क्रमों के माध्यमों से जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन योजनाओं में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, संवहनीय कृषि, स्वास्थ्य, हिमालयी पारितंत्र परिरक्षण, संवहनीय पर्यावास विकास, हरित भारत, तथा जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट मिशन शामिल हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) सभी जलवायु कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारत ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस तथा कोएलिशन फॉर डिजास्टर-रिसाइलियेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभायी है।

(घ) भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए विकास की दिशा में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास हो, और निम्नलिखित तरीकों से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाते हुए वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके:

- वर्ष 2030 तक, भारत में इलेक्ट्रिक पॉवर की कुल स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत हिस्से को गैर-जीवाश्म स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाए।
- वर्ष 2030 तक, कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करके GDP के वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45 प्रतिशत घटाया जाए।
- परंपरा एवं संरक्षण और आधुनिकीकरण मूल्यों पर आधारित स्वस्थ एवं संवहनीय जीवनशैली को आगे बढ़ाया एवं प्रसारित किया जाए, जिसमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए एक प्रमुख तरीके के रूप में LiFE - लाइफस्टाइल फॉर एनवार्यनमेंट का जन आंदोलन चलाया जाना शामिल है।

****